शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 16 – 23 नवम्बर 2026 मूल्य पांच रूपये

केंद्र से 2,531 करोड़ रुपये अधिक मिले, फिर भी 4,139 करोड़ बढ़ा राजकोषीय घाटा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना से पता चलता है कि सरकार को केंद्र से अतिरिक्त धनराशि मिलने के बावजूद प्रदेश का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है। सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटा 9,698.03 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन संशोधित अनुमान में यह बढ़कर 13,836.84 करोड़ रुपये हो गया है। यानी इसमें 4,138.81 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह करीब 42.7 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय दस्तावेज के अनुसार केंद्र से प्रदेश को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 2,229.59 करोड़ रुपये और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 301.68 करोड़ रुपये अधिक मिलने का अनुमान है। इस तरह केंद्र से कुल 2,531.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद घाटे का बढ़ना बताता है कि प्रदेश के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर कम नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि अतिरिक्त धनराशि मिलने के बाद भी सरकार वित्तीय स्थिति को संभालने में क्यों सफल नहीं हो पा रही है।

सरकार की आमदनी में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन खर्च उससे भी अधिक बढ़ा है। बजट में राजस्व प्राप्तियां 40,361.30 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था, जिसे संशोधित कर 43,732.46 करोड़ रुपये किया गया है। यानी आमदनी में 3,371.16 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है। दूसरी ओर राजस्व खर्च 46,938.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 52,175.39 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसमें 5,237.08 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आमदनी और खर्च के इसी अंतर के कारण राजस्व घाटा भी 6,577.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,442.93 करोड़ रुपये हो गया है। यानी राजस्व घाटे में 1,865.92 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सरकार ने खर्च बढ़ने के पीछे कई कारण बताए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, अनुदान, आपदा राहत के तहत राज्य की हिस्सेदारी, हिमकेयर योजना और न्यायालयों के आदेशों से जुड़े भुगतान शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च में 800.08 करोड़ रुपये, पेंशन में 866.48 करोड़ रुपये और ग्रेच्युटी में 1,339.46 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं वेतन पर खर्च में 667.20 करोड़ रुपये की कमी दिखाई गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार पर पेंशन और अन्य अनिवार्य भुगतानों का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

प्रदेश सरकार ने पूंजीगत खर्च भी बढ़ाया है। बजट में इसके लिए 7,987.87 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर 10,292.30 करोड़ रुपये किया गया है। इस मद में 2,304.43 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार के अनुसार यह धनराशि पेयजल योजनाओं, भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और आईटीआई जैसी विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। हालांकि विकास कार्यों के लिए खर्च बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ यह भी देखना होगा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश को भविष्य में कितनी आर्थिक और सामाजिक राहत मिलती है।

वित्तीय स्थिति के सामने एक और बड़ी चुनौती राजस्व घाटा अनुदान का बंद होना है। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश को इस मद में 3,257 करोड़ रुपये मिले थे। अब यह सहायता नहीं मिलने से सरकार पर अपनी आमदनी बढ़ाने और खर्च नियंत्रित करने का दबाव और बढ़ेगा।

सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कर और गैर-कर राजस्व में सुधार, केंद्र की योजनाओं का अधिक लाभ लेने, बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, अनावश्यक खर्च घटाने और टोल बैरियरों की ई-नीलामी जैसे कदम उठाने की बात कही है। बिजली बिक्री से होने वाली आमदनी को भी बढ़ी हुई गैर-कर आय का एक प्रमुख कारण बताया गया है। गैर-कर राजस्व का अनुमान 3,946.21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,786.10 करोड़ रुपये किया गया है।

प्रदेश का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 2,77,497 करोड़ रुपये रखा गया है और संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा इसके 4.99 प्रतिशत तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास कार्यों को जारी रखते हुए कर्ज और खर्च पर नियंत्रण रखने की है। सरकार ने वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बढ़ता राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटे में वृद्धि और केंद्र से मिलने वाली राजस्व घाटा सहायता का बंद होना इस लक्ष्य को कठिन बनाता है। अब देखना होगा कि सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के दावों को कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर उतार पाती है।

प्रदेश में 14,754 शिक्षक पद खाली शिक्षा सुधार के दावे किसके भरोसे?

50 डे-बोर्डिंग स्कूलों में एक में भी पढ़ाई शुरू नहीं 3,100 नई भर्तियां पांच साल के निश्चित मानदेय पर, नियमितीकरण का प्रावधान नही

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए सरकारें योजनाएं और घोषणाएं तो करती रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इनका लाभ विद्यार्थियों को जमीन पर कितना मिला। पूर्व भाजपा सरकार के अटल आदर्श विद्यालयों का अनुभव सामने है। अब मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार के सीबीएसई स्कूलों और डे-बोर्डिंग स्कूलों की योजना पर भी यही सवाल उठने लगे हैं। क्या नई योजनाएं भी घोषणाओं, बजट और निर्माण की फाइलों तक सीमित रह जाएंगी, या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वास्तव में बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी?

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने पहले बजट में 10 और अगले बजट में 15 अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की थी। शुरुआत में इसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया। लेकिन कई साल बाद भी इन स्कूलों की निर्माण स्थिति और नियमित संचालन को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है।

अब सुक्खू सरकार ने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की योजना शुरू की है। जुलाई 2026 में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 158 स्कूलों को मंजूरी और 146 को सीबीएसई संबद्धता मिलने की जानकारी दी थी। 29 अक्तूबर को सरकार ने सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। इनमें अंग्रेजी और गणित के 600 तथा अन्य विषयों के 2,500 शिक्षक शामिल हैं। कंप्यूटर विषय के 120 शिक्षक भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। चयन राज्य चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा से होना है और तय मानदेय 30 हजार रुपये प्रतिमाह रखा गया है। लेकिन इन नियुक्तियों की अवधि पांच वर्ष बताई गई है और नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल केवल पद भरने का नहीं, बल्कि यह भी है कि पांच साल बाद इन शिक्षकों और स्कूलों की व्यवस्था का क्या होगा? क्या सरकार स्थायी शिक्षक उपलब्ध कराने के बजाय अस्थायी नियुक्तियों पर निर्भर रहेगी?

डॉ. जनक राज के विधानसभा प्रश्न के जवाब में सरकार ने साफ किया कि सीबीएसई स्कूलों की विशेष योजना के तहत नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी जवाब में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के 150 स्वीकृत पदों में से 117 भरे होने की जानकारी दी गई। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों में

शेष पृष्ठ 8 पर.....

युवाओं को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी:राज्यपाल

वृंदावन में श्री दयाराम बद्री केदार उत्तराखंड आश्रम का लोकार्पण

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए आधुनिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का 'विरासत के साथ विकास' का दृष्टिकोण भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है।

राज्यपाल ने वृंदावन में श्री दयाराम बद्री केदार उत्तराखंड आश्रम का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विकास और केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य देश की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी प्राचीन सभ्यता, धार्मिक परंपराओं और सेवा, करुणा तथा सद्भाव जैसे मूल्यों से है। वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण की भूमि है, जो प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश देती है।

राज्यपाल ने आश्रम की स्थापना



में परम पूज्य श्री कमलनयन जी महाराज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आश्रम केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा का केंद्र भी होना चाहिए।

उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड के सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों राज्य देवभूमि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे संस्थान 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के साथ आधुनिक शिक्षा और तकनीक के प्रति जागरूक बनाने पर भी जोर दिया। आश्रम में गुरुकुल शिक्षा, संस्कृत अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई।

केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश ने बांटी डिग्रियां

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह धर्मशाला में आयोजित किया गया। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य



अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए।

समारोह में राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों और स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने की नई शुरुआत है। विद्यार्थियों को जीवन में ईमानदारी, विनम्रता और सीखने की भावना बनाए रखनी चाहिए। डिग्री व्यक्ति को पहचान दिलाती है, लेकिन उसका चरित्र और संस्कार उसे स्थायी सम्मान दिलाते हैं।

राज्यपाल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियों पर शोध को प्राथमिकता देने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर विश्वविद्यालयों को ठोस समाधान विकसित करने चाहिए। हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य प्रकृति के अनुकूल होने चाहिए।

उन्होंने विश्वविद्यालय में हिमालयी पर्यावरण, जल संसाधन, जनजातीय समुदायों, प्राकृतिक खेती और पर्यटन से जुड़े शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ने की आवश्यकता बताई।

राज्यपाल ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की अधिक संख्या पर प्रसन्नता जताते हुए इसे महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढ़ती उपलब्धियों का प्रमाण बताया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल, उद्यमिता, नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण में लगाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विश्वविद्यालयों को केवल परिसर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ग्रामीण समुदायों, स्कूलों और उद्योगों के साथ जुड़कर समाज की समस्याओं के समाधान में योगदान देना चाहिए।

पर्यटन से रोजगार बढ़े लेकिन पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान न पहुंचे :राज्यपाल

गेयटी थिएटर में विंटर ट्रैवल एग्जीबिशन शुरू, टिकाऊ पर्यटन पर जोर

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में विंटर ट्रैवल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया। ट्रैवल एंड टूरिज्म बाजार, कोलकाता की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया गया।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन विकास का मतलब केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि पर्यटन गतिविधियों से जंगलों, नदियों, जल स्रोतों और पहाड़ों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। पर्यटन ऐसा होना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के अवसर मिलें तथा प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहे।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदर्शनी का विषय 'यात्रा एवं पर्यटन उद्योग में सतत विकास का महत्व' है। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, झीलें, ऐतिहासिक स्थल और आध्यात्मिक परंपराएं इसे पर्यटन के लिए विशेष पहचान देते हैं। राज्यपाल ने गोवा की



भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि इससे दोनों राज्यों को पर्यटन के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसी पहल स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रदर्शनी पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के बीच नए संपर्क और साझेदारी विकसित करेगी तथा हिमाचल को जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गंतव्य बनाने में मदद करेगी।

आरकेएमवी के वार्षिक समारोह में छात्राओं से राष्ट्र निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आहवान

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने महिलाओं से राजनीति, प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए आगे आने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी केवल शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें नीति निर्धारण और देश के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।



राज्यपाल राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित और आत्मविश्वास से भरी महिलाएं राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में आगे आकर समाज को नई दिशा दे सकती हैं। महिला सशद्रिकरण तभी पूरा होगा, जब बेटियों को बिना भेदभाव आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे।

उन्होंने हिमाचल की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ी ऋतु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर का विशेष उल्लेख किया।

राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ते नशे, विशेषकर चिट्टे की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने छात्राओं से स्वयं नशे से दूर रहने और परिवार तथा समाज को जागरूक कर नशामुक्त हिमाचल अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।

उन्होंने छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और अनुसंधान जैसे क्षेत्रें में दक्षता हासिल करने के लिए भी प्रेरित किया। समारोह में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

ऊर्जा संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता में 2.38 लाख विद्यार्थियों ने लिया भाग

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने एसजेवीएन की ओर से ऊर्जा संरक्षण पर आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता-2026 के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण कम करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जागरूक करने के लिए विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और एसजेवीएन मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता के पहले चरण में कक्षा पांचवीं से सातवीं और आठवीं से दसवीं तक के 2,38,548 विद्यार्थियों



जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे बदलाव भी ऊर्जा बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 21 वर्षों से स्कूली बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता के साथ समाज को ऊर्जा बचाने का संदेश दे रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रगति की है। 31 जुलाई 2026 तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 300.50 गीगावाट पहुंच गई थी, जो कुल स्थापित क्षमता का 54 प्रतिशत से अधिक है। देश ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

राज्यपाल ने विजेताओं को बधाई दी और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर एसजेवीएन के निदेशक (कार्मिक) अजय शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं) राजेश चंदेल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

चैतड़ू में 18.29 करोड़ से बना एसटीपीआई केंद्र शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा



जिले में गग्गल हवाई अड्डे के पास चैतड़ू में 18.29 करोड़ रुपये की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र का उद्घाटन किया। सरकार को उम्मीद है कि इस केंद्र से अगले पांच वर्षों में 350 से 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 15 से 20 नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस केंद्र में आईटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यहां 106 प्लग-एंड-प्ले सीटें, 5,031 वर्ग फुट का इन्क्यूबेशन स्पेस और प्रबंधकों के लिए चार केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा 40 लोगों की क्षमता वाला सभागार, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम और नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आईटी और निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए आईटी कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और नए स्टार्टअप को सुविधाएं दी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि चैतड़ू में एसटीपीआई केंद्र बनने से कांगड़ा के युवाओं और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रदेश में ही काम करने के अवसर मिलेंगे। इससे युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम होगी। इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा, विधायक सुरेश कुमार और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

धर्मशाला कॉलेज के नाम के आगे जुड़ सकता है 'सेंटेनरी', मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

शिमला/शैल। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के 100 वर्ष पूरे



होने पर इसके नाम के आगे 'सेंटेनरी' शब्द जोड़ने पर प्रदेश सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने महाविद्यालय की ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ओएसए) की इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री महाविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1926 में स्थापित इस संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके 100 वर्षों का सफर प्रदेश के शैक्षणिक और सामाजिक विकास से जुड़ा रहा है।

ओएसए ने मुख्यमंत्री के सामने महाविद्यालय से जुड़ी अन्य मांगें भी रखीं। इनमें भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील पाइन क्षेत्र का स्थायी संरक्षण और एसोसिएशन के लिए कॉलेज परिसर में कार्यालय बनाने की मांग शामिल है। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया।

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। किसी संस्थान की पहचान उसके पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान से बनती है।

इस अवसर पर ओएसए अध्यक्ष संजीव गांधी सहित सांसद अनुराग शर्मा, पूर्व मंत्री विप्लव ठाकुर, आर. एस. बाली और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हल्दी और गेहूं का एमएसपी बढ़ाएगी सरकार:मुख्यमंत्री

हल्दी का समर्थन मूल्य 170 और गेहूं का 90 रुपये प्रति किलो होगा, किसानों की मासिक आय 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य कृषि को किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनाना है। इसके लिए अगले वर्ष से हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य



(एमएसपी) 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये और गेहूं का 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा। सरकार किसानों की मासिक आय 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार वित्तीय नुकसान के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा के लिए सीधे उनके खातों और हाथों में पैसा पहुंचा रही है। उन्होंने किसानों से जमीन नहीं बेचने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार में फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर एमएसपी की व्यवस्था शुरू की गई है। दूध को भी इसके दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि ढगवार में 300 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है। यहां प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा और किसानों का परिवहन खर्च भी सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने वाइल्डफ्लावर हॉल से 401 करोड़ रुपये मिलने, कड़छम-वांगतू परियोजना की रॉयल्टी 12 से 18 प्रतिशत होने और बीबीएमबी से सालाना 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलने को सरकार की उपलब्धियां बताया। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया।

एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 1,000 इलेक्ट्रिक बसें : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाएगी। सरकार 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी और आने वाले वर्षों में भी निगम के बेड़े में नई बसें शामिल की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के मझयार में सेरा से हमीरपुर के लिए नए बस रूट का शुभारंभ किया। इस सेवा से हमीरपुर, नादौन, सेरा और आसपास के गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। खासकर डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जोल सप्पड़ आने-जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कम खर्चीला है। इससे एचआरटीसी की परिचालन लागत घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि, प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन मुश्किल है, वहां डीजल बसें भी चलती रहेंगी। सरकार दोनों तरह की बसों के बीच संतुलन बनाकर परिवहन व्यवस्था मजबूत करेगी।

अब पता चला जमीन भी सोना उगलती है प्राकृतिक खेती से किसानों की बढ़ी आमदनी

टांडा में मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान किसानों ने साझा किए अनुभव, एमएसपी मिलने से खाली पड़ी जमीन पर फिर शुरू हुई खेती

शिमला/शैल। प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलने से हिमाचल के किसानों का खेती के प्रति रुझान बढ़ रहा है। कांगड़ा जिले के टांडा में आयोजित प्राकृतिक खेती किसान सम्मेलन में किसानों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अब उनकी मेहनत का उचित दाम मिल रहा है। प्रागपुर के एक किसान ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान कहा, अब पता चला कि जमीन भी सोना उगलती है।

किसान ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों का भुगतान सीधे बैंक खाते में आने से उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है। लंबागांव के पुनीचंद राणा ने बताया कि पहले उनके क्षेत्र में 70 से 80 प्रतिशत जमीन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने के बाद किसान हल्दी उगाने लगे हैं। अब हल्दी को बीज के रूप में बेचकर भी आमदनी हो रही है।

भेड़ू ब्लॉक के राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष पांच क्विंटल गेहूं और डेढ़ क्विंटल हल्दी सरकार को बेची। धर्मशाला की गीता देवी ने कहा कि अपनी जमीन नहीं होने के बावजूद वह लीज पर जमीन



लेकर प्राकृतिक खेती कर रही हैं।

नूरपुर के एक किसान ने आम के बगीचों में खाली जमीन पर हल्दी उगाकर अतिरिक्त कमाई करने की जानकारी दी। बैजनाथ के नवेंद्र कटोच ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर भूमि पर किसान रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं।

किसानों ने कहा कि फसलों और दूध के लिए एमएसपी की व्यवस्था से खेती को दोबारा आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने में मदद मिल रही है।

ढगवार दुग्ध संयंत्र का जनवरी 2027 में होगा लोकार्पण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले



के ढगवार में निर्माणाधीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस संयंत्र का लोकार्पण जनवरी 2027 में किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर जिलों के हजारों दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। यहां मोजरेला चीज, पनीर, दही, घी और मक्खन जैसे उत्पाद तैयार कर 'हिम' ब्रांड के तहत बाजार में बेचे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने दुग्ध सहकारी समितियों के पंजीकरण में तेजी लाने और अधिक किसानों को उनसे जोड़ने को कहा। सरकार संयंत्र के डिजिटलीकरण के लिए 1.25 करोड़ रुपये और संचालन के लिए 29.49 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार होगा।

बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही कर्तव्य है जितना अच्छाई के साथ सहयोग करना।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

चुनावी हथियार बनकर क्यों रह गए भ्रष्टाचार के आरोप?



हिमाचल की राजनीति में भी भ्रष्टाचार के आरोप सत्ता हासिल करने का हथियार बन चुके हैं। विपक्ष में रहते हुए नेता घोटालों के दस्तावेज लहराते हैं, दोषियों को जेल भेजने का ऐलान करते हैं और सत्ता में आते ही जांच करवाने का वादा करते हैं। लेकिन कुर्सी मिलते ही वही मामले सरकारी फाइलों में उलझ जाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही पुरानी जांचों का शोर फिर सुनाई देने लगता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई भी अब चुनावी कैलेंडर से तय होगी?

हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ चार्जशीटें सौंपी हैं। वर्ष 2012 में कांग्रेस ने प्रेम कुमार धूमल सरकार पर आरोप लगाए। भाजपा ने 2013 और 2016 में वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ चार्जशीट दी। दिसंबर 2016 की चार्जशीट में मुख्यमंत्री सहित 41 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। जयराम ठाकुर सरकार के समय कांग्रेस ने 27 दिसंबर 2018 को 22 पन्नों की चार्जशीट में 35 मुद्दे उठाए। फिर 29 अक्तूबर 2022 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 'लूट की छूट' नाम से 23 पन्नों की चार्जशीट जारी की। इसमें पुलिस भर्ती पेपर लीक, कोविड काल में मेडिकल उपकरणों की खरीद, जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद, खनन और आउटसोर्स भर्तियों में कथित अनियमितताओं के आरोप शामिल थे।

दिसंबर 2022 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां कीं और फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भंग कर दिया। लेकिन आयोग भंग होने से पूरे मामले की जवाबदेही तय नहीं होती। प्रश्नपत्र बेचने वाले नेटवर्क, कथित लेन-देन और इसमें शामिल लोगों की जांच कहां तक पहुंची? कितने आरोपियों के खिलाफ अदालत में मामला पहुंचा? सरकार को इस मामले की मौजूदा स्थिति और अंतिम कारवाई का ब्यौरा देना चाहिए। कोविड काल में मेडिकल उपकरणों की खरीद मामले में सरकारी खजाने को हुए नुकसान और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों व कंपनियों की भूमिका का पूरा हिसाब सामने नहीं आया। जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी जांच का परिणाम सार्वजनिक नहीं है। यदि अनियमितताएं हुई तो जिम्मेदार कौन है और यदि आरोप गलत थे तो सरकार ने इसकी स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी?

दूसरी ओर, भाजपा ने दिसंबर 2024 में कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 18 कथित घोटालों और अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर जांच एजेंसियों ने क्या कारवाई की? भाजपा को भी इसका जवाब देना चाहिए।

अब कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार के बड़े टेंडर, सरकारी खरीद, खर्च और जमीन आवंटन की जांच के लिए सात मंत्रियों की कैबिनेट सब-कमेटी गठित कर रही है। बद्दी में लीज पर दी गई जमीन का मामला भी इसके दायरे में है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आरोप है कि पिछली सरकार के समय करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में दी गई। यदि ऐसा हुआ है तो सरकार को जमीन आवंटन के दस्तावेज, वास्तविक मूल्य, लीज की शर्तें और सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि जांच पूरी करने और जिम्मेदारी तय करने की समयसीमा क्या है।

सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस सरकार की जवाबदेही का है। दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद अपनी ही चार्जशीट में लगाए आरोपों की जांच चार साल में पूरी क्यों नहीं हुई? मई 2023 में गठित जांच व्यवस्था को अब फिर सक्रिय करने की जरूरत क्यों पड़ी? जिन विधायकों और अन्य लोगों के खिलाफ पहले से जांच चल रही है, उनके मामलों का नतीजा कब आएगा?

भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीरता का पैमाना आरोपों की संख्या नहीं, कारवाई का परिणाम है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को बताना होगा कि उनके लगाए आरोपों में कितने सही साबित हुए, कितने मामलों में दोषियों को सजा मिली और सरकारी धन की कितनी वसूली हुई। यदि हर चुनाव से पहले भ्रष्टाचार की फाइलें खुलें और चुनाव के बाद फिर बंद हो जाएं, तो यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, केवल सत्ता के लिए है।

राफेल सौदा:भारत को लड़ाकू विमान के साथ तकनीकी निर्भरता भी चाहिए



गौतम चौधरी

रक्षा सौदों की सफलता केवल विमानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता से नहीं मापी जानी चाहिए। असली कसौटी यह है कि भारी निवेश के बाद भारत को कितनी तकनीकी स्वतंत्रता और सामरिक संप्रभुता हासिल होती है।

भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी चल रही है। करीब 30 अरब यूरो के इस प्रस्ताव को भारत के सबसे बड़े रक्षा खरीद कार्यक्रमों में गिना जा रहा है। इतनी बड़ी राशि केवल विमानों की खरीद का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय करदाताओं के पैसे, देश की औद्योगिक क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी है।

12 फरवरी 2026 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इस प्रस्ताव को प्रारंभिक स्वीकृति दी थी। योजना के अनुसार अधिकांश विमानों का निर्माण भारत में होना है। इससे रोजगार, स्थानीय उद्योग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। जून 2025 में डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के बीच हुए समझौते के तहत हैदराबाद में राफेल के प्रमुख ढांचागत हिस्सों का निर्माण भी प्रस्तावित है। वर्ष 2028 से उत्पादन शुरू होने की अपेक्षा है। यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए सकारात्मक कदम है। हालांकि विमान का ढांचा भारत में बनना और उसकी मूल तकनीक पर भारत का अधिकार होना दो अलग-अलग बातें हैं।

इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इंजन और संवेदनशील तकनीक का हस्तांतरण है। राफेल में फ्रांस की सफ्रान कंपनी का M88 इंजन इस्तेमाल होता है। 13 फरवरी 2026 को सफ्रान के CEO ओलिवियर एंड्रीस ने भारत में इंजन की असेंबली लाइन स्थापित करने की बात कही थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि इंजन के सबसे संवेदनशील हिस्सों का निर्माण फ्रांस में ही होगा। नवंबर 2026 में फ्रांसीसी अखबार ''Le Quotidien des Entreprises'' ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि सफ्रान और डसॉल्ट भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जो और विमान की मूल डिजाइन पर फ्रांस अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।

इसका अर्थ है कि भारत में विमान और इंजन के कुछ हिस्सों का निर्माण तो होगा, लेकिन उनकी मूल तकनीक पर भारत को पूर्ण अधिकार मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। असेंबली और तकनीक हस्तांतरण में यही अंतर है। यदि महत्वपूर्ण पुर्जो के निर्माण, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए भारत को लगातार फ्रांस पर निर्भर रहना पड़े तो स्थानीय उत्पादन के बावजूद आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी।

इस सौदे का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारतीय स्वदेशी हथियारों का राफेल के साथ एकीकरण है। भारत ने अस्त्र, रुद्रम और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW) जैसे आधुनिक हथियार विकसित किए हैं। अक्तूबर 2026 की मीडिया रिपोर्टो के अनुसार डसॉल्ट भारतीय हथियारों को राफेल में एकीकृत करने के लिए सहमत हुई है। यह सकारात्मक संकेत है। इससे क्त्क्व और भारतीय रक्षा उद्योग की उपलब्धियों को विदेशी लड़ाकू विमान पर इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि किसी स्वदेशी मिसाइल को विमान में लगाने की अनुमति मिलना और भविष्य में भारत का स्वयं नई मिसाइल को विमान से जोड़ पाने की क्षमता हासिल करना अलग-अलग बातें हैं। इसके लिए विमान और हथियार के बीच तकनीकी संवाद स्थापित करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट (ICD) कहा जाता है। इनके माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक अपने हथियारों के एकीकरण में अधिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर विमान का मूल सॉफ्टवेयर, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसी संवेदनशील तकनीक फ्रांस के नियंत्रण में रहने की संभावना है। ऐसे में भविष्य में नए हथियार जोड़ने या तकनीकी बदलाव करने के लिए विदेशी कंपनी पर निर्भरता बनी रह सकती है।

यह निर्भरता युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष महत्व रखती है। पहले से एकीकृत और प्रमाणित भारतीय हथियारों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने नियंत्रण में कर सकती है। लेकिन युद्ध के दौरान विकसित किसी नए हथियार को राफेल में जोड़ने या उसकी तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत पड़े तो विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता सामने आ सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और फ्रांस के बीच अप्रैल 2025 में नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों का समझौता हुआ था। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में भारतीय हथियारों के एकीकरण के लिए तकनीक हस्तांतरण का उल्लेख है। सफ्रान ने भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA के इंजन विकास में DRDO के साथ संयुक्त काम और व्यापक तकनीक हस्तांतरण की पेशकश भी की है। हालांकि इस संबंध में अंतिम समझौता होना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी शर्तें और सीमाएं समझना आवश्यक है।

भारत की वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। स्वदेशी विमान निर्माण कार्यक्रमों को पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए विदेशी विमानों की खरीद की आवश्यकता को खारिज नहीं किया जा सकता। राफेल की आधुनिक युद्धक क्षमताएं भारतीय वायुसेना के लिए उपयोगी हो सकती हैं। समस्या विमान खरीदने में नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी दीर्घकालीन तकनीकी निर्भरता में है।

रक्षा सौदों का उद्देश्य केवल तात्कालिक सैन्य जरूरत पूरी करना नहीं होना चाहिए। उनसे देश की वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षमता भी मजबूत होनी चाहिए। फ्रांस के लिए अपनी संवेदनशील तकनीक की रक्षा करना स्वाभाविक है। उसी तरह भारत के लिए अपने करदाताओं के धन और सामरिक संप्रभुता की रक्षा करना अनिवार्य है।

114 विमानों का प्रस्ताव अभी अंतिम खरीद समझौते में नहीं बदला है। इसलिए इसकी अंतिम कीमत और तकनीक हस्तांतरण की शर्तो पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिर भी यह सुनिश्चित होना चाहिए कि भारत केवल विदेशी विमान का बाजार बनकर न रह जाए। उसे विमान के साथ हथियारों के एकीकरण, रखरखाव और भविष्य के तकनीकी उन्नयन की पर्याप्त स्वतंत्रता भी मिले।

आखिरकार, रक्षा आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेशी हथियारों का बहिष्कार नहीं, बल्कि ऐसी क्षमता हासिल करना है कि भारत अपनी सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश की तकनीकी इच्छा पर निर्भर न रहे। राफेल सौदे की वास्तविक सफलता भी इसी कसौटी पर तय होनी चाहिए।

सोभा सिंह – एक दिव्य कलाकार

प्रख्यात चित्रकार की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष

लेखक:राजेश चंद्र बाली

सरदार सोभा सिंह हृदय से एक सच्चे कलाकार थे। एक ऐसे कलाकार, जिनकी सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था और सौंदर्य, अच्छाई तथा मानवीय मूल्यों के प्रति उनका चिरस्थायी दर्शन भी उन्हें उनकी अमर कलाकृतियों के माध्यम से जीवंत बनाए हुए है वे कृतियां जो उनके शाश्वत चित्रों के फ्रेम से बाहर आकर मानो स्वयं बोल उठती हैं। वे भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित समकालीन कलाकारों में से एक रहे हैं।

पाश्चात्य तैल चित्रकला (Western oil painting) की शास्त्रीय विधियों का उपयोग करते हुए इस महान चित्रकार ने अनेक कालजयी कृतियां रचीं। उन्होंने सिख इतिहास और पंजाबी लोककथाओं के महत्वपूर्ण पात्रों के अत्यंत मार्मिक और अविश्वसनीय रूप से सजीव चित्र उकेरे। सोभा सिंह की चिरस्थायी कलाकृतियों में सिख गुरु, पैगंबर, संत और पौराणिक व्यक्तित्व जीवंत हो उठते हैं।

यद्यपि उनकी कला मुख्य रूप से प्रसिद्ध धार्मिक और प्रेम-प्रसंगों को दर्शाती है, किंतु उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रथम गुरु, श्री गुरु नानक देव जी की है, जिसमें वे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाए हुए हैं यह चित्र ईश्वर में आस्था रखने वाले प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद प्रदान करता है। हालांकि, उनका पहला चित्र छठे सिख गुरु, श्री हरगोबिंद साहिब जी का था।

''सोहनी-महिवाल'' और सम्राट शाहजहां की बाहों में मुमताज महल की उनकी सर्वव्यापी कृति जिसका शीर्षक ''लास्ट डिजायर ऑफ मुमताज महल'' (मुमताज महल की अंतिम इच्छा) है प्रेम का वास्तविक चित्रण हैं। सोहनी-महिवाल अविभाजित पंजाब की एक प्रसिद्ध दुखांत प्रेम कहानी है, जिसने सोभा सिंह को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वे इस कथा से इतने अभिभूत थे कि 1937 और 1980 के बीच उन्होंने इस चित्र के पांच अलग-अलग संस्करण बनाए। इनमें से पहला चित्र 1937 में बनाया गया था, जिसे वे 1947 के विभाजन के दौरान लाहौर में ही छोड़ आए थे।

जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, उसी प्रकार सोभा सिंह की कल्पनाशक्ति और सीधे उनके हृदय से निकले रंगों का चुनाव, उनकी कलाकृतियों को निहारने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आंखों को अपार आनंद प्रदान करता है।

यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि एक स्थापित और प्रख्यात चित्रकार बनने से पहले वे ब्रिटिश-भारतीय सेना में तीसरी पीढ़ी के सैनिक थे। उनका जन्म 29 नवंबर, 1901 को गुरदासपुर जिले में ब्यास नदी के तट पर बसे एक छोटे से कस्बे श्री हरगोबिंदपुर में माता बीबी अछरां देवी और पिता सरदार देवा सिंह के घर हुआ था। उनके पिता सेना की 22वीं बटालियन में सर्वेयर होने के साथ-साथ एक प्रशिक्षित घुड़सवार सैनिक (कैवेलियर) और प्रतिभाशाली चित्रकार भी थे। उनके दादा, सरदार चरहत सिंह भी महाराजा रणजीत सिंह की सेना में घुड़सवार सैनिक थे।

सोभा सिंह मात्र 15 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने बहनोई से चित्रकला सीखना शुरू किया और बाद में 1915 में अमृतसर के इंडस्ट्रियल स्कूल से कला एवं शिल्प (Art & Craft) में एक वर्षीय पाठयक्रम में दाखिला लिया। हालांकि, 1919 से 1923 तक ब्रिटिश-भारतीय सेना में मुख्य मानचित्रकार (Head Draughtsman) के रूप में 5 वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से चित्रकला के अपने जुनून को अपनाया। इस अवधि के दौरान मानचित्र बनाने के साथ-साथ उन्होंने अपनी चित्रकला के कौशल को भी निखारा।

1923 में बीबी इंदर कौर से विवाह के पश्चात, उन्होंने अमृतसर के फव्वारा चौक पर ''सुभाष स्टूडियो'' खोला। उनके स्टूडियो का नाम महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित था। 1925 से 1929 के बीच लाहौर के अनारकली में ''इको स्कूल ऑफ आर्ट'' (Echo School of Art) की स्थापना करने के बाद उन्होंने एक सफल चित्रकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। 1935 में उनके दो चित्रों का ''लंदन इलस्ट्रेटेड वीकली'' में शामिल किया गया। यह दिलचस्प बात है कि सोभा सिंह, जब सेना के प्रचार विभाग (Publicity Department) में मुख्य कलाकार के रूप में कार्यरत थे, ने 1945 के ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन के लिए पोस्टर भी बनाए थे।

सोभा सिंह के पौत्र डॉ. हिरदय पाल सिंह ने इस लेखक से बातचीत में बताया कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 1947 में विभाजन की पूर्व संध्या पर उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा और वे अपने लगभग 300 कलाकृतियो जिनमें साठ अमूल्य चित्र शामिल थे तथा अन्य कीमती सामान को वहीं पीछे छोड़ आए।

अंतत: वे हिमाचल की कांगड़ा घाटी स्थित पालमपुर के शांत गांव अंद्रेटा में बस गए और अपनी विभिन्न उत्कृष्ट कृतियों के माध्यम से इस छोटे से गांव को अंतरराष्ट्रीय कला मानचित्र पर ला खड़ा किया। ''सोभा सिंह आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम'' स्थापित है, जिसका प्रबंधन उनकी पुत्री बीबी गुरचरण कौर और उनके पुत्र डॉ. हिरदय पाल सिंह परिवार द्वारा किया जा रहा है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह शांत स्थान कला प्रेमियों और उनके प्रशंसकों को उस युग में वापस ले जाता है, जब सोभा सिंह जी ने जीवन के अत्यंत करीब दिखने वाले सजीव चित्र बनाए थे। इनमें सिख गुरुओं के प्रतिष्ठित चित्रों के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय व्यक्तित्वों, पंजाब और हिमाचल की दुल्हनों तथा हिमालय के आदिवासी समुदायों के चित्र शामिल हैं। उनके चित्र अपनी आध्यात्मिक गहराई, सौंदर्य उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों के माध्यम से आज भी पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं।

1973 में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस प्रख्यात भारतीय कलाकार के जीवन और 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी पर आधारित ''पेंटर ऑफ द पीपल'' (Painter of The People) नामक एक वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री फिल्म) बनाया। इसे प्रसार भारती के आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म ''वेव्स'' पर देखा जा सकता है

सोभा सिंह जी को 1983 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''पद्म श्री'' से अलंकृत किया गया। भारत सरकार के डाक विभाग ने 29 नवंबर, 2001 को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

इस वर्ष 27 नवंबर को इस महान कलाकार की 125वीं जयंती के अवसर पर, पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित उनकी जन्मभूमि श्री हरगोबिंदपुर से वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ होगा, जिसका समापन नवंबर 2027 में हिमाचल प्रदेश के अंद्रेटा स्थित उनकी कर्मभूमि में होगा। ये समारोह ''जन्मभूमि से कर्मभूमि'' विषय (थीम) पर केंद्रित होंगे।

सोभा सिंह मेमोरियल आर्ट सोसाइटी (SSMAS), अंद्रेटा द्वारा भारतीय कला प्रेमियों के प्रति कलाकार के उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करने के लिए इन समारोहों में विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के सहयोग से कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

सोसाइटी के महासचिव डॉ. हिरदय पाल सिंह ने बताया कि समारोहों की शुरुआत नवंबर के दूसरे पखवाड़े में बठिंडा में कला महोत्सवों के साथ होगी। सोसाइटी 27 नवंबर को श्री हरगोबिंदपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें धार्मिक समागम और स्कूली छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलाकार के जीवन के विभिन्न चरणों में उनसे जुड़े रहे परिवारों के वंशजों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष ''कृतज्ञता समारोह'' भी प्रस्तावित है।

डॉ. पॉल ने बताया कि 2027 में अंद्रेटा स्थित उनके ऐतिहासिक स्टूडियो में सोभा सिंह की एक सिलिकॉन प्रतिमा का अनावरण भी किया जाना है। सोसाइटी कलात्मक उत्कृष्टता के सम्मान में एक उत्कृष्ट कलाकार को ''सोभा सिंह कला पुरस्कार'' प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखती है।

सोभा सिंह के कुछ प्रसिद्ध कथन हैं: ''गुरु नानक मेरी साधना की अभिव्यक्ति हैं। चित्रकला मेरा जीवन है। गुरु मेरे प्राण-रक्त हैं। मैंने लोगों को प्रेरित करने के लिए गुरुओं के चित्र बनाए हैं। गुरु का चित्रण करना मेरे वास्तविक स्व के विकास के चरम के सबसे निकट है ''और''धर्म आस्था के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जनमानस को भौतिकवादी दर्शन के माध्यम से शिक्षित नहीं किया जा सकता। वे धर्म के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। '' सिख परिवारों में बुजुर्ग पिता तुल्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले सम्मानजनक उपनाम ''दारजी'' के रूप में प्रसिद्ध सरदार सोभा सिंह जी, अपने नाम ''सोभा'' (जिसका अर्थ है गरिमा/आभा) के अनुरूप, चार दशक पूर्व 22 अगस्त, 1986 को इस संसार को अलविदा कह गए, और अपने पीछे ऐसी अमिट स्मृतियां छोड़ गए जो अपनी गरिमामयी कलाकृतियों के माध्यम से कला के इतिहास और विश्व भर के कला प्रेमियों को सदैव सुशोभित और मंत्रमुग्ध करती रहेंगी।

(लेखक एक भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारी हैं और वर्तमान में आकाशवाणी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जालंधर में क्षेत्रीय समाचार प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं)

पांगी में प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित जौं में पांच गुना से अधिक की वृद्धि

पिछले साल के 99.74 क्विंटल की तुलना में इस वर्ष हुई 542.86 क्विंटल की सरकारी खरीद

राज्य सरकार द्वारा 8000 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की बदौलत जौं की खेती बनी घाटी के किसानों की पहली पसंद

जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी में प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद को लेकर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कई गुना अधिक किसान इस पारंपरिक फसल की खेती को प्रमुख नकदी फसल के रूप में अपनाने के लिए आगे आये हैं जिसका असर वर्ष 2026 की सरकारी खरीद के आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है।



वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों से कुल 99.74 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उत्पादित जौ की खरीद की गई थी। उस दौरान किसानों को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से करीब 5.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया था,जबकि वर्ष 2026 में सरकारी खरीद के लिए किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 172 किसानों ने 542.86 क्विंटल जौं की पैदावार 80 रूपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकर को बेची है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद व्यवस्था के प्रति किसानों का रुझान और भरोसा बढ़ा है।

हालांकि पांगी घाटी में जौ लबे समय से पारंपरिक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है मगर पहले स्थानीय किसान इसकी पैदावार नकदी फसल के रूप में नहीं कर रहे थे। 15 अप्रैल 2025 को उपमंडल मुख्यालय की किलाड़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने पांगी घाटी को प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया तथा घाटी की प्रमुख पैदावार जौं को 60 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। वर्ष 2026 में इसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर 80 रूपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया। प्रदेश सरकर की इस प्रशंसनीय पहल से न केवल किसानों की आय मे निरंतर बढ़ोतरी हो रही है बल्कि घाटी की बल्कि पारंपरिक फसलों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल रहा है ।

उल्लेखनीय है कि जैसे ही राज्य सरकार ने पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया। इसके उपरांत कृषि विभाग और आत्मा परियोजना द्वारा निरंतर किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जीवामृत, प्राकृतिक खाद तैयार करने और फसलों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप घाटी में किसानों की रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने के साथ-2 बड़ी संख्या में स्थानीय किसान जौं व अन्य नकदी फसलों की प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं तथा उनकी आय में निरंतर इजाफा हो रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम पांगी अमनदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जौं का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद घाटी के किसानों और बागवानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है तथा इससे किसानों की आर्थिकी मजबूत करने के साथ-साथ घाटी के लोगों के लिए स्वरोजगार व अतिरिक्त आय का एक नया माध्यम बना है।

कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नायक ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभागीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। घाटी के ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक तरीके से जौ उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान जौं की सरकारी खरीद योजना का लाभ उठा सकें।

246 पंचायतों में चिट्टा तस्करों और नशे के शिकार लोगों की होगी पहचान

15 दिसंबर तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश, 159 तस्कर जेल भेजे, 92 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त

शिमला/शैल। हिमाचल में चिट्टे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार ने अब संवेदनशील पंचायतों पर निगरानी बढ़ाने और तस्करों की पहचान करने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सभी



जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को 15 दिसंबर से पहले चिट्टे के लिहाज से रेड कैटेगरी में रखी गई 246 पंचायतों की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

इस दौरान नशा तस्करों के साथ-साथ चिट्टे की गिरफ्त में आए लोगों की भी पहचान होगी।

धर्मशाला के तपोवन में आठवीं राज्य स्तरीय एनकोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल तस्करों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे के शिकार लोगों के इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था भी जरूरी है। उन्होंने निजी नशा मुक्ति केंद्रों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी है।

सरकार के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत 159 लोगों को जेल भेजा गया है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में नशा तस्करी से अर्जित करीब 92 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। तस्करी में संलिप्त 21 पुलिसकर्मियों और दूसरे विभागों के 30 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है।

दिसंबर में 'खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान शुरू होगा। एनडीपीएस मामलों के जल्द निपटारे के लिए दो नए न्यायालय भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में जवाबदेही तय कर संगठित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को शपथ दिलाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश



विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज राय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री ने पंकज राय को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी तथा उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नवनियुक्त अध्यक्ष निष्ठा, ईमानदारी एवं दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के नियामक ढांचे को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

सुख-आश्रय योजना के 41 बच्चों को पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के तपोवन से मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 41 बच्चों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बच्चे कांगड़ा जिले के चार बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं।

भ्रमण दल में सलियाणा संस्थान के 11, तितली के नौ, दाड़ी के पांच और गरली संस्थान के 16 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए उनके साथ आवश्यक स्टाफ भी भेजा गया है।

पांच दिवसीय यह यात्रा पालमपुर से शुरू होगी। इस दौरान बच्चों को दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। यात्रा के दौरान उनके रहने और खाने की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनाथ और असहाय बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसे भ्रमण से बच्चों को देश के इतिहास, संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का मौका मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 20 विद्यार्थियों के लिए गोवा में भी शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने की योजना है। सरकार भविष्य में भी बच्चों के लिए ऐसी पहल जारी रखेगी।

धर्मशाला मैराथन 2.0 का एंथम लॉन्च, 2,000 धावकों को जोड़ने का लक्ष्य

3 से 42 किलोमीटर तक दौड़ की पांच श्रेणियां होंगी, फिटनेस के साथ चिट्टे के खिलाफ भी चलेगा जागरूकता अभियान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित समारोह में धर्मशाला मैराथन 2.0 का आधिकारिक एंथम लॉन्च किया।



उन्होंने मैराथन की जर्सी और मेडल का भी अनावरण किया। कांगड़ा वैली कार्निवल-2026 के तहत होने वाली इस मैराथन में अब तक 850 से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। आयोजकों ने 20 दिसंबर तक देशभर से 2,000 से अधिक धावकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को चिट्टे जैसे नशे के खिलाफ जागरूक करना है। मैराथन के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मैराथन में अलग-अलग आयु वर्गों के लिए 3, 5, 10, 20 और 42 किलोमीटर की पांच श्रेणियां रखी गई हैं। इसके पहले संस्करण में करीब 1,300 धावकों ने हिस्सा लिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार पर 2,600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़ने और पर्यटकों के लिए हेली-टैक्सी सेवा शुरू करने की दिशा में भी काम हो रहा है।

उन्होंने बताया कि धर्मशाला मैराथन के रूट को एआईएमएस प्रमाणन दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप बनाया जा सके।

गुरु नानक देव जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गुरु नानक देव जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पर्व सिखों का सबसे पवित्र त्योहार है। सिखों के प्रथम गुरु, श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस पर यह पर्व मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने विश्व बंधुत्व के बंधन को मजबूत करने के लिए प्रेम, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और निःस्वार्थ सेवा का उपदेश दिया। उनके उपदेशों में उनकी शिक्षाओं का सार निहित है और वर्तमान में यह शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हैं।

सरकार के फैसलों से प्रदेश के राजस्व में 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी: सुक्खू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों



और फैसलों से हिमाचल प्रदेश के राजस्व में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के साथ विकास कार्यों को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले के गलोड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने और स्थानीय सहकारी समिति को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम पंचायत गोईस के नए पंचायत भवन के लिए भी आर्थिक सहायता देने की बात कही।

मुख्यमंत्री के अनुसार, किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में हिमाचल ने अपनी शर्तों के अनुसार समझौता किया है। इससे प्रदेश को परियोजना में निवेश नहीं करना पड़ेगा और निर्माण पूरा होने के बाद सालाना 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर वर्तमान सरकार अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। अगले एक वर्ष में इसे बेहतर चिकित्सा संस्थानों में शामिल करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने और परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की प्रस्तावित योजना का भी उल्लेख किया।

उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस सरकार के चार वर्ष पूरे होने का समारोह सुजानपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र से आपदा राहत के घोषित 1,500 करोड़ रुपये जारी नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।

एचपीपीसीएल ने चार वर्षों में 3,459 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने दिसंबर 2022 से पिछले चार वर्षों के दौरान 3,459.99 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर 1,387.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। प्रदेश सरकार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग कर हिमाचल को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

एचपीपीसीएल की सैंज जलविद्युत परियोजना ने 1,252.56 मिलियन यूनिट बिजली बनाकर 462.55 करोड़ रुपये का राजस्व दिया। वहीं सावरा-कुड्डू परियोजना से 1,190.38 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ और 589.6 करोड़ रुपये की आय हुई। काशांग चरण-I परियोजना ने 776.32 मिलियन यूनिट बिजली बनाकर 252 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पेखुबेला, भंजाल, अघलौर और बेरा डोल से भी बिजली उत्पादन किया गया।

प्रदेश में नई परियोजनाओं का निर्माण भी जारी है। किन्नौर की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना अप्रैल 2027 तक पूरी होने की संभावना है। इसके अलावा काशांग चरण-II और III तथा चांजू-III परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेणुकाजी बांध परियोजना की डायवर्जन टनल का निर्माण भी जारी है।

सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पिछले चार वर्षों में 47 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जबकि 29.6 मेगावाट की परियोजनाओं का निर्माण जारी है। 1 मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का काम भी चल रहा है, जिसके फरवरी 2027 तक शुरू होने की संभावना है।

एचपीपीसीएल ने पिछले चार वर्षों में कौशल विकास, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर 19.25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

टांडा मेडिकल कॉलेज में 23.53 करोड़ की 3 – टेस्ला एमआरआई मशीन शुरू

256 स्लाइस सीटी स्कैन और रोबोटिक सर्जरी सुविधा देने का भी मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

शिमला / शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 23.53 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित 3 – टेस्ला एमआरआई मशीन जनता को समर्पित की। इस मशीन के शुरू होने से मरीजों को गंभीर और जटिल बीमारियों की जांच के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। नई मशीन से शरीर के अंदरूनी हिस्सों की अधिक साफ तस्वीरें मिलेंगी, जिससे बीमारी की सही पहचान और उपचार में मदद मिलेगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में पहले से 1.5 – टेस्ला एमआरआई मशीन काम कर रही है। नई मशीन लगने से जांच की क्षमता बढ़ेगी और मरीजों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने मेडिकल क लेज में एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्स – रे की जांच बिना लंबी प्रतीक्षा के उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन और आधुनिक रोबोटिक सर्जरी उपकरण उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीजी मेडिकल सीटों की संख्या 277 से बढ़कर 597 हो गई है। इस वर्ष 320 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज में 28 सफल किडनी प्रत्यारोपण किए जाने पर चिकित्सकों की सराहना भी की।

शाहपुर में 11.50 करोड़ से बने 100 बिस्तरों के अस्पताल का लोकार्पण

स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता 35 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का दावा, डॉक्टरों के 400 पद भरेः सुक्खू

शिमला / शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के शाहपुर में 11.50 करोड़ रुपये की लागत से बने 100 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 35 प्रतिशत कर्मचारी उपलब्ध थे। वर्तमान सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर करीब 70 प्रतिशत कर दी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में डॉक्टरों के 400 पद भरे जा चुके हैं और जल्द ही अतिरिक्त सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें डॉक्टरों और विशेषज्ञों की तैनाती कर लोगों को बेहतर इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों को आगे और मजबूत किया जाएगा।

इस अवसर पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अस्पताल भवन के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि शाहपुर में पुलिस थाना और आईटीआई का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे।

निवेश को आसान बनाने के लिए नया कानून, अब मंजूरियों में देरी पर अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा सिंगल विंडो प्राधिकरण, जमीन से लेकर डिजिटल मंजूरियों तक कई नए प्रावधान, निवेश और रोजगार के सरकारी दावों की असली परीक्षा अब अमल में

शिमला / शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। सरकार इसे प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों के लिए मंजूरियों की प्रक्रिया आसान बनाने की बड़ी पहल बता रही है। हालांकि, इस कानून की असली सफलता इस बात से तय होगी कि निवेश के प्रस्ताव कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं और युवाओं को वास्तव में कितना रोजगार मिलता है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह विधेयक विधानसभा में पेश किया। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो निवेश प्रस्तावों की मंजूरी और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। विभिन्न विभागों की मंजूरियों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल और एक ही आवेदन की व्यवस्था होगी।

विधेयक में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान है। आवेदन निर्धारित समय में न निपटाने पर अपील की व्यवस्था होगी। वहीं, पात्र निवेशकों को स्व – प्रमाणन और कुछ मंजूरियों के स्वतः नवीनीकरण की सुविधा मिलेगी।

सरकार औद्योगिक जमीन का लैंड बैंक बनाने, नए औद्योगिक क्षेत्र और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इसे पारदर्शी निवेश व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नया कानून प्रदेश में निवेश की वास्तविक बाधाओं, महंगी ढुलाई, जमीन की उपलब्धता और रोजगार की कमी को दूर कर पाएगा? इसका जवाब कानून के प्रावधानों से नहीं, बल्कि उसके जमीन पर लागू होने से मिलेगा।

शिमला में ग्रामीण भारत महोत्सव शुरू, 10 राज्यों के उत्पादों के 40 स्टॉल सजे

शिमला / शैल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पदमदेव कॉम्प्लेक्स, रिज शिमला में ग्रामीण भारत महोत्सव – 2026 का शुभारंभ किया गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया ने महोत्सव का उद्घाटन किया। यह आयोजन 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 10 राज्यों के ग्रामीण कारीगरों और उत्पादक समूहों के 40 स्टॉल लगाए गए हैं।

महोत्सव में स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, बुनकरों और ग्रामीण कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के 14 स्टॉलों पर स्पीति के सीबकथॉर्न उत्पाद, कुल्लू का धातु एवं काष्ठ शिल्प, चंबा चप्पल, किन्नौरी ऊनी वस्त्र, पांगी की जड़ी – बूटियां, मंडी की सेरा – बड़ियां, सोलन का बांस शिल्प और शिमला के सेब उत्पाद उपलब्ध हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जम्मू – कश्मीर की बसोहली पश्मीना, गुजरात की कच्छ कढ़ाई, राजस्थान के पारंपरिक उत्पाद, पंजाब की फुलकारी और उत्तराखंड के ऊनी वस्त्र सहित विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प भी प्रदर्शित किए गए हैं।

डॉ. विवेक पठानिया ने कहा कि महोत्सव ग्रामीण उत्पादकों को सीधे बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने का माध्यम है। इससे कारीगरों को ग्राहकों की पसंद समझने और नए व्यावसायिक संबंध बनाने का अवसर मिलेगा।

महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता, पारंपरिक शिल्प और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। यह आयोजन 'वोकल फॉर लोकल' और विकसित भारत – 2047 के लक्ष्य को भी प्रोत्साहित करेगा।

बच्चों का 5 और 15 वर्ष की आयु में आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी

30 सितंबर 2027 तक 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए सुविधा पूरी तरह निःशुल्क, स्कूलों में लगाए जा रहे शिविर

शिमला / शैल। बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराना जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार बच्चों का पहला बायोमेट्रिक अपडेट 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर और दूसरा अपडेट 15 वर्ष की आयु में करवाना अनिवार्य है। इसमें उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और चेहरे की पहचान से जुड़ी जानकारी अपडेट की जाती है।

बच्चों के बड़े होने के साथ उनके शारीरिक लक्षणों में बदलाव आता है। ऐसे में पुरानी बायोमेट्रिक जानकारी के कारण भविष्य में आधार से पहचान करवाने में परेशानी हो सकती है। इसका असर छात्रवृत्ति, स्कूल – कॉलेज में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं और आधार से जुड़ी दूसरी सेवाओं पर भी पड़ सकता है।

UIDAI ने 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह अपडेट 30 सितंबर 2027 तक पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। इस दौरान अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बच्चों के स्कूलों में भी आधार अपडेट के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अभिभावक शिविरों की तारीख और समय की जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रशासन से प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा नजदीकी आधार सेवा केंद्र या अधिकृत आधार केंद्र पर भी यह अपडेट करवाया जा सकता है। UIDAI के आधार सेवा केंद्र सप्ताह के सातों दिन खुले रहते हैं, हालांकि सेवाएं निर्धारित समय और उपलब्धता के अनुसार मिलेंगी। UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित उम्र में बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं और निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाएं।

नौणी विश्वविद्यालय में डिजिटल औद्यानिकी और ड्रोन तकनीक का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा

शिमला / शैल। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए नौणी स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में डिजिटल औद्यानिकी और ड्रोन तकनीक का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम आईटीआई लिमिटेड के सहयोग से करीब 350 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

इस केंद्र में ड्रोन के माध्यम से फसलों की निगरानी, कृषि से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण, किसानों को डिजिटल सलाह और फलों में कीटनाशकों के अवशेषों की जांच जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। शुरुआत में सेब, अनार और अन्य प्रमुख बागवानी फसलों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, उत्पादन से लेकर बाजार में बिक्री तक फलों की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी।

प्रस्ताव के अनुसार, आईटीआई लिमिटेड केंद्र के लिए वित्तीय संसाधन, उपकरण, तकनीकी स्टाफ और जरूरी ढांचा उपलब्ध करवाएगा। विश्वविद्यालय पर इसके निर्माण और संचालन का खर्च नहीं पड़ेगा। उसे वार्षिक संस्थागत साझेदारी शुल्क भी दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एच.एस. बवेजा के अनुसार, इस पहल से किसानों को नई तकनीक का लाभ मिलेगा और बागवानी को अधिक आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। दोनों संस्थानों के बीच एमओयू पर 1 दिसंबर 2026 को हस्ताक्षर प्रस्तावित हैं।

आइस स्केटिंग रिंक में नए सीजन की तैयारियां शुरू, क्लब खुद करेगा सफाई

शिमला / शैल। ऐतिहासिक शिमला आइस स्केटिंग रिंक में नए सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्ष 2026 – 27 का स्केटिंग सीजन समय पर शुरू करने के लिए क्लब प्रबंधन ने मैदान की सफाई खुद करवाने का फैसला लिया है।



दिवाली के दौरान मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई गई थीं। त्योहार खत्म होने के बाद भी मैदान में कचरा और पटाखों का बचा हुआ सामान पड़ा है। क्लब ने संबंधित अधिकारियों से मैदान की सफाई करवाने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई। इसके बाद क्लब ने अपने स्तर पर सफाई करने का निर्णय लिया है।

क्लब के कार्यकारिणी सदस्य सुदीप महाजन ने बताया कि शनिवार से सफाई का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद रिंक को स्केटिंग के लिए तैयार किया जाएगा। क्लब चाहता है कि सर्दियों में तापमान अनुकूल होते ही बर्फ जमाने का काम शुरू हो और स्केटिंग गतिविधियां समय पर शुरू हो सकें। इससे शहर के लोगों के साथ – साथ शिमला घूमने आने वाले पर्यटक भी इस पारंपरिक शीतकालीन खेल का आनंद ले सकेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सरकार की रोजगार गारंटी के दावों पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हर साल एक लाख रोजगार देने की गारंटी अब सरकार के अपने विधानसभा जवाब के आंकड़ों के कारण सवालों के घेरे में है। सत्ता में आने से पहले युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार ने विधानसभा में विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के जवाब मे 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक विभिन्न विभागों में खाली पदों और दी गई नियुक्तियों का विवरण दिया है। दस्तावेज के विभागवार आंकड़ों के जोड़ के अनुसार प्रदेश में लगभग 58,234 पद रिक्त हैं, जबकि इसी अवधि में नियुक्तियों का आंकड़ा लगभग 13,438 है। यानी सरकार के कार्यकाल में रोजगार देने की रफ्तार और खाली पदों की संख्या के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है।

सरकार के जवाब में नियुक्तियों को नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतन और प्रशिक्षु आधार पर अलग- अलग दिखाया गया है। इसमें लगभग 6,457 नियुक्तियां नियमित आधार पर, 5,822 अनुबंध आधार पर और 1,102 दैनिक वेतन आधार पर दर्ज हैं। इसके अलावा प्रशिक्षु और अन्य श्रेणियों में भी नियुक्तियां हुई हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार के रोजगार संबंधी आंकड़ों में सभी नियुक्तियां स्थायी सरकारी नौकरियां नहीं हैं। अनुबंध और दैनिक वेतन पर काम करने वाले युवाओं को नियमित कर्मचारियों जैसी नौकरी की सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलतीं। ऐसे में सवाल उठता है कि एक लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने की गारंटी के मुकाबले स्थायी नौकरियां कितनी दी गई?

रिक्त पदों का विभागवार ब्यौरा देखें तो शिक्षा विभाग की स्थिति सबसे चिंताजनक है। स्कूल शिक्षा विभाग में 13,182 पद खाली हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 6,021 पद रिक्त हैं। यह स्थिति बताती है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

लोक निर्माण विभाग में 19,457 पद खाली बताए गए हैं। पुलिस विभाग में 3,822 पद रिक्त हैं। इनमें आरक्षी के 2,315, मुख्य आरक्षी के 701, उपनिरीक्षक के 220, सहायक उपनिरीक्षक के 176 और निरीक्षक के 45 पद शामिल हैं। पशुपालन विभाग में 2,009, वन विभाग में 1,400 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 874 पद खाली हैं। जल शक्ति विभाग में 670, आयुष विभाग में 621, राज्य कर एवं आबकारी विभाग में 542 और कृषि विभाग में 318 पद रिक्त हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 314 और तकनीकी शिक्षा विभाग में 285 पद खाली हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है।

नियुक्तियों के ब्यौरे में भी नियमित रोजगार के बजाये अनुबंध और अस्थायी व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सामने आता है। बिजली बोर्ड में 1,449 नियुक्तियां अनुबंध आधार पर दर्ज हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 554 अनुबंध और 505 दैनिक वेतन आधार पर नियुक्तियां दिखाई गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में 40 नियमित और 197 अनुबंध नियुक्तियां दर्ज हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में 690 अनुबंध और एक दैनिक वेतन आधार पर नियुक्ति का विवरण है। उच्च शिक्षा विभाग में 125 नियमित प्राचार्य और 496 अनुबंध आधार पर आचार्य नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। स्कूल शिक्षा विभाग में 4,294 नियुक्तियां अनुबंध अथवा प्रशिक्षु आधार पर दर्ज हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या सरकार स्थायी रोजगार देने के बजाय अस्थायी नियुक्तियों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है?

सरकार ने रोजगार के सवाल के जवाब में स्वरोजगार योजनाओं का विवरण भी दिया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 31 जुलाई 2025 तक 67 युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलने की जानकारी दी गई है। कौशल विकास भत्ता योजना के तहत वर्ष 2013 से 31 जुलाई 2025 तक 82,208 युवाओं के नामांकन का आंकड़ा दिया गया है। उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3,373 लाभार्थियों को 594.73 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 4,982 लाभार्थियों और स्टार्टअप योजना के तहत 279 युवाओं को वित्तीय सहायता दी गई। मत्स्य पालन विभाग ने 1,277 और उद्यान विभाग ने 2,129 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करने की जानकारी दी है। लेकिन इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या को सीधे नई सरकारी नौकरियों की संख्या नहीं माना जा सकता।

विधानसभा में रखे गए इस दस्तावेज ने सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब कांग्रेस ने हर साल एक लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी तो अब तक कितने युवाओं को नियमित नौकरी मिली? कितने युवाओं को अनुबंध और दैनिक वेतन पर रखा गया? हजारों पद खाली रहने के बावजूद उन्हें भरने की प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं आई? क्या स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों और प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को भी रोजगार की गारंटी के आंकड़ों में शामिल किया जा रहा है?

जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर उठे सवाल

शिमला/शैल। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कौल सिंह नेगी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र विवाद में एसडीएम रामपुर की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 16 अगस्त 2022 को तहसीलदार रामपुर द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। अदालत ने तहसीलदार रामपुर के 29 अक्तूबर 2022 के आदेश को भी निरस्त कर दिया। यह फैसला केवल प्रमाण पत्र की वैधता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रमाण पत्र जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया, राजस्व अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और सरकारी रिकॉर्ड के सत्यापन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

यह विवाद वर्ष 2022 में उस समय सामने आया था, जब कौल सिंह नेगी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई। अपीलकर्ता प्रीतम देव की ओर से दलील दी गई कि कौल सिंह नेगी और उनके पिता के पास पहले से किन्नौर जिले के निचार क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र मौजूद हैं। ऐसे में रामपुर से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पुराने प्रमाण पत्रों और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जांच की जानी चाहिए थी।

अदालत के सामने यह तथ्य भी आया कि कौल सिंह नेगी का परिवार किन्नौर जिले के नानस्पो गांव का निवासी बताया गया है, जबकि रामपुर के लहासा क्षेत्र में उनका वर्तमान निवास है। राजस्व रिकार्ड में उनकी जाति को लेकर अलग- अलग प्रविष्टियां भी सामने आई। एक रिकॉर्ड में 'किन्नौरा कोली' और दूसरे में केवल 'कोली' का उल्लेख था। अदालत ने माना कि इन दोनों प्रविष्टियों के बीच अंतर की जांच संबंधित सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा की जानी जरूरी थी।

फैसले में तहसीलदार रामपुर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। अदालत के अनुसार, प्रमाण पत्र जारी करते समय किन्नौर के संबंधित राजस्व अधिकारियों से आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया गया। इसके अलावा अपीलकर्ता की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर भी पर्याप्त विचार नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्ष को प्रभावी सुनवाई का उचित अवसर देना जरूरी था।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र में कथित गलत जानकारी देने या तथ्यों को छिपाने के आरोपों पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किसी पक्ष को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसलिए इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने कौल सिंह नेगी की जातीय पहचान पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। आदेश में उन्हें सक्षम प्राधिकारी, जिला किन्नौर के समक्ष नए सिरे से आवेदन करने की छूट दी गई है। अब संबंधित अधिकारी निर्धारित नियमों और मूल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उनकी पात्रता पर निर्णय ले सकेंगे।

इस फैसले ने प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में प्रशासनिक जवाबदेही और दस्तावेजों के निष्पक्ष सत्यापन की जरूरत को फिर से सामने ला दिया है। अदालत का स्पष्ट संदेश है कि आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और ठोस राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद ही जारी किए जाने चाहिए।

प्रदेश में 14,754 शिक्षक पद खाली

.....पृष्ठ 1 का शेष

कंप्यूटर प्रवक्ताओं के 1,641 स्वीकृत पदों में से 976 खाली बताए गए। यानी एक तरफ कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपये देने की बात भी कही थी। अब यह बताना जरूरी है कि कितनी लैब वास्तव में स्थापित और चालू हो चुकी हैं।

कंप्यूटर शिक्षकों का मामला इससे भी गंभीर है। करीब 1,300 शिक्षक वर्ष 2001-02 से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। लगभग 25 साल सेवा देने के बाद भी उनका भविष्य स्पष्ट नहीं है। मंत्रिमंडल ने उन्हें सीमित सीधी भर्ती कोटे का लाभ देने का निर्णय लिया है, लेकिन यह नियमित नियुक्ति नहीं है। दूसरी ओर, सरकार ने विशेष योजना के तहत नियुक्त 1,922 शिक्षकों को नियमित सरकारी पदों में समायोजित करने से भी इन्कार किया है। इससे शिक्षकों की भर्ती नीति और सरकारी स्कूलों में स्थायी स्टाफ की उपलब्धता पर सवाल खड़े होते हैं।

डे-बोर्डिंग स्कूलों की घोषणा भी अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। शिक्षा मंत्री के विधानसभा जवाब के अनुसार 33 विधानसभा क्षेत्रों में 50 स्कूल मंजूर किए गए हैं। इनमें 13 नए भवन बनने हैं और 37 मौजूदा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। लेकिन एक नवंबर 2026 तक एक भी डे-बोर्डिंग स्कूल शुरू नहीं हुआ था। बाकी 23 विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्ताव विचाराधीन बताए गए। जब मंजूर 50 स्कूलों में से एक भी चालू नहीं हुआ, तो बाकी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इस सुविधा के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा?

प्रदेश में एक नवंबर तक 82,547 स्वीकृत शिक्षक पदों में से 14,754 खाली थे। इनमें 4,008 जेबीटी और 976 कंप्यूटर विज्ञान प्रवक्ताओं के पद शामिल थे। ऐसे में केवल सीबीएसई का दर्जा देने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। सरकार को बताना होगा कि कितने स्कूल नियमित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों, कंप्यूटर लैब और जरूरी सुविधाओं के साथ चल रहे हैं। अब घोषणाएं नहीं, स्कूलवार प्रगति रिपोर्ट चाहिए। वरना सीबीएसई और डे-बोर्डिंग स्कूलों की योजनाएं अधूरी उम्मीद बनकर रह सकती हैं।